Statement

Demand and Allocation of Foodgrains to Rajasthan and Orissa Month-wise from December,

1992

(figures in 000 tonnes)

	Wheat		Rice	
	Demand	Allocation	Demand	Allocation
RAJASTHAN				
December, 1992	200.00	101.50	5.00	3.60
January, 1993	200.00	94.00	5.00	11.50
February, 1993	200.00	94.00	3.00	11.5
March, 1993	146.50	89.00	3.00	11.50
ORISSA				
December, 1992	35.00	20.00	35.00	36.25
January, 1993	35.00	20.00	35.00	38.75
February, 1993	35.00	20.00	30.00	38.75
March, 1993	35.00	20.00	30.00	38.70

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु एक रूप नीति की आवश्यकता

2296. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में एकरूप नीति के अभाव में प्रादेशिक स्तर पर आम उपभोक्ताओं के हितों की पर्याप्त रक्षा नहीं की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें रोष फैल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में इस संबंध में एकरूप नीति का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी नहीं । केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उपभोक्ताओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए प्रमुख आवश्यक वस्तुयें पहुंचाने के लिए पूरी तरह एकजुट हो कर कार्य करते हैं । हाल के वर्षों में देश में, मिट्टी के तेल , आयातित खाद्य तेल, लेवी चीनी तथा साफ्टकोक के अलावा प्रति वर्ष 170 से 180 लाख मी० टन खाद्यान्न वितरित किए गए हैं । इस समय लगभग 4 लाख उचित दर की दुकानों का एक व्यापक तंत्र मौजूद है, जिनमें से लगभग तीन-चौथाई दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं ।